

(2023) 2 एस0सी0आर0 276

नंद लाल और अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

[आपराधिक अपील संख्या. 1421/2015]

14, मार्च 2023

[बी0आर0 गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल, जे0जे0]

दंड संहिता , 1860: धारा 302 - हत्या - अभियोजन का मामला कि अभियुक्तों और शिकायतकर्ता के बीच पिछली दुश्मनी थी। अभियुक्त सं0 11 ने शिकायतकर्ता पर हमला किया और उसके बाद, शिकायतकर्ता ने एक प्राथमिकी दर्ज की । अभियुक्त ने फिर घातक हथियारों से लैस अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर एक गैरकानूनी जनसमूह बनाई , और अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साथ पीड़ित-शिकायतकर्ता के पिता पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मौत हो गई - के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्तों को दोषी ठहराया जाना। अन्य अपराधों के साथ 302 और निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रमाणिकता अभिनिर्धारित- घायल व्यक्ति द्वारा एफआईआर दर्ज करने में देरी के संबंध में बिल्कुल नहीं बताया गया। अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दबाने का प्रयास किया। अभियुक्त को लगी चोट के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था, जिसे मामूली या सतही नहीं माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी छिपाई कि अभियुक्त ने पुलिस को सूचित किया कि शिकायतकर्ता ने उस पर हमला किया था , इस प्रकार, उक्त अभियुक्त संदेह के लाभ पाने का हकदार है - जहाँ तक शेष अभियुक्तों का संबंध है , उनके नाम का उल्लेख मर्ज रिपोर्ट में नहीं किया गया था जो कि एफआईआर दर्ज करने से पहले मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं घटनास्थलीय पंचनामा में दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज करने में देरी को ध्यान में रखते हुए, उनके नाम नहीं दिए जाने की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्कालिन दस्तावेजों में उनके नाम का उल्लेख नहीं होने की स्थिति में, उक्त अभियुक्तों को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है - उनकी सजा केवल पर्याप्त पुष्टि के बिना हितबद्ध साक्षी की मौखिक साक्ष्य पर आधारित थी , इस प्रकार, पोषणीय नहीं होगी - उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया गया।

न्यायालय ने अपील स्वीकार किया।

अभिनिर्धारित: 1.1 एफआईआर की सामग्री पर विश्वास करते हुए कि घटना रात लगभग 08.30 बजे हुई है और घायल व्यक्ति लगभग 10-11 बजे बाजार पहुंचे थे, जहां उन्हें सूचित किया गया था कि जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, उनका इलाज नहीं किया जा सकता है, एफआईआर दर्ज करने में लगभग चार से पांच घंटे की और देरी होने के कारण का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। बाजार और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यह अभिलेख में आया है कि दोनों स्थानों को जोड़ने वाली एक बारहमासी सड़क है। इसलिए बाजार से पुलिस स्टेशन पहुंचने में अधिकतम 30-40 मिनट का समय लगेगा। एफआईआर दर्ज करने में हुई चार घंटे की देरी को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया गया है। [कंडिका 25][286-एफ-जी]

1.2 निर्विवाद रूप से, अभियुक्त संख्या 11 को लगी चोटों को मामूली या ऊपरी नहीं माना जा सकता है। साक्षी, हितबद्ध साक्षी भी होते हैं, क्योंकि वे मृतक के करीबी रिश्तेदार होते हैं। यह अभिलेख में आया है कि दोनों परिवारों के बीच सरपंच के चुनाव को लेकर पहले से दुश्मनी थी। पिछली दुश्मनी दोधारी तलवार है। एक ओर, यह मकसद प्रदान कर सकता है और दूसरी ओर, गलत निहितार्थ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। [कंडिका 28][288-डी-ई]

1.3 4 नवंबर 2006 को सुबह 03.15 बजे एफआईआर दर्ज करने से बहुत पहले पुलिस, अभियुक्त संख्या 11 को मेडिकल जांच के लिए ले गई थी। चिकित्सा पदाधिकारी को अभियुक्त संख्या 11 का चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अग्रेषित करने वाले मेमो में उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त संख्या 11 ने पुलिस को सूचित किया था कि लगभग 08.30 बजे, साक्षी सं0 -1 द्वारा उस पर हमला किया गया था। निर्विवाद रूप से, अभियोजन पक्ष ने उक्त घटना के संबंध में जानकारी छिपाई है। अभियोजन पक्ष ने साक्षी सं0 -1 द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को भी दबा दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दबाने का प्रयास किया है। मामले के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त संख्या 11 को लगी चोटों के गैर-स्पष्टीकरण के साथ, अभियुक्त संख्या 11 संदेह का लाभ पाने का हकदार है। [कंडिका 29][288-ई-जी]

1.4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक मामले में, एफआईआर दर्ज करने में देरी अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं होगी। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, यह मानते हुए कि घटना रात 08.30 बजे हुई थी और घायल व्यक्ति रात 10-11 बजे के बीच बाजार में थे, और यह ध्यान में रखते हुए कि बाजार से पुलिस स्टेशन की दूरी 15 किलोमीटर है, एफआईआर दर्ज करने में चार घंटे का विलम्ब अभियोजन पक्ष के मामले की वास्तविकता पर गंभीर संदेह पैदा करेगा। यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त संख्या 11 किसी भी मामले में, रात्री 11.45 बजे से पूर्व ही पुलिस को घटना के बारे में सूचित कर चुका था। साक्षी सं0-1 द्वारा उस पर हुए हमले के संबंध में उसके

द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को दबाना, साथ ही अभियुक्त संख्या 11 के खिलाफ साक्षी सं0-1 द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को दबाना भी संदेह को बढ़ाता है। [कंडिका 30][289-बी-डी]

1.5 साक्षी सं0 2 और 9 घायल साक्षी हैं। ऐसे में उनकी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता। हालाँकि, पिछली दुश्मनी सिद्ध होने की स्थिति में, झूठे आरोप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। मौजूदा मामले में , यह देखा जाएगा कि अभियुक्त संख्या 12 के पूरे परिवार को इसमें फंसाया गया है। हालांकि साक्षी सं0-2 ने अपनी जिरह में अभियुक्त की पहचान की है और उसका नाम बताया है , उसने कहा है कि , हालांकि उसने अभियुक्तों के रिश्तेदारों को पहचान लिया है, उसे उनके नाम याद नहीं हैं। ऐसे में अभियुक्त संख्या 12 के पूरे परिवार को फंसाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। [कंडिका 34][291-बी-सी]

1.6 अभियुक्त संख्या 8, 9 और 10 के नाम मर्ज रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं हैं , जो एफआईआर दर्ज करने से पहले दर्ज की गई थी , इसलिए उनके नाम मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन और घटना स्थलिय पंचनामे में भी नहीं पाए गए हैं। प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी और समसामयिक दस्तावेजों में उनके नाम का उल्लेख नहीं होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए , उक्त अभियुक्तों को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पर्याप्त पुष्टि के बिना , केवल हितबद्ध साक्षियों की मौखिक साक्ष्य के आधार पर इन अभियुक्तों की सजा पोषणीय नहीं होगी। [कंडिका 35][291-सी-ई]

1.7 अभियोजन पक्ष ने साक्षी सं0 -3, साक्षी सं0 -5, साक्षी सं0 -6 और साक्षी सं0 -8 का परीक्षण किया है, जिनमें से किसी ने भी अभियोजन ने मामले का समर्थन नहीं किया है। पीडब्लू 2, 9 और 13 के अनुसार , यह साक्षी सं0-3 ही था जिसने घायल व्यक्तियों को बाजार तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की थी। हालाँकि , उन्होंने कहा है कि यद्यपि साक्षी सं0 -2 उन्हें घटना के बारे में सूचित करने के लिए उनके पास आई थी , लेकिन उन्होंने उन्हें यह नहीं बताया था कि किस आरोपी ने मृतक और घायल व्यक्तियों के साथ मारपीट की थी। इस प्रकार , उक्त अपीलकर्ता भी संदेह का लाभ पाने के हकदार होंगे। [कंडिका 36][291-ई-एफ]

लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य (1976) 4 एससीसी 394 ; राजस्थान राज्य बनाम माधो और अन्य (1991) 2 सप्लीमेंट एससीसी 396 ; मप्र राज्य बनाम मिश्रीलाल (मृत) और अन्य (2003) 9 एससीसी 426 ; नागरथिनम और अन्य बनाम राज्य (पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व) (2006) 9 एससीसी 57: [2006] 3 एससीआर 833 ; रामाशीष रे बनाम जगदीश सिंह (2005) 10 एससीसी 498 ; रमेश बाबूराव देवस्कर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 13 एससीसी 501: [2007] 11 एससीआर 197 ; वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य [1957] एससीआर 981 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

- (1976) 4 एससीसी 394 कंडिका 26 को संदर्भित करता है
- (1991) 2 सप्लीमेंट एससीसी 396 कंडिका 27 को संदर्भित करता है
- (2003) 9 एससीसी 426 कंडिका 27 को संदर्भित किया गया
- [2006] 3 एससीआर 833 कंडिका 27 को संदर्भित करता है
- (2005) 10 एससीसी 498 कंडिका 28 में संदर्भित
- [2007] 11 एससीआर 197 कंडिका 31 को संदर्भित करता है
- [1957] एससीआर 981 में कंडिका 32 का उल्लेख है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1421/2015

सीआरएलए संख्या 529/2008 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.11.2014 से।

साथ

आपराधिक अपील संख्या 1470/2017 और 775-776/2023।

रेन्जिथ. बी. मरार, शैलेन्द्र तिवारी, (ए.सी.), विकास उपाध्याय, सुश्री अंकिता कश्यप, रेन्जिथ बी., लक्ष्मी एन. कैमल, सुश्री आशु जैन, दवेश कु. शर्मा, अरुण पूमुल्ली, अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण।

सुमीर सोढ़ी, ध्रुव वाधवा, देवाशीष तिवारी, प्रतिवादी के लिए अधिवक्तागण।

बी0आर0 गवई, जे0 द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

1. एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6134-6135/2019 की सुनवाई हेतु अनुमति दी गई।
2. ये अपीलें बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित 11 नवंबर 2014 के फैसले और आदेश पर चुनौती देती हैं, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील खारिज कर दी जाती है और द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा 24 मई 2008 को पारित फैसले और आदेश की पुष्टि की जाती है (बाद में इसे "विचारणीय न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया जाएगा), भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, "भा0द0वी0") की धारा 302 एवं अन्य दंडनीय अपराधों के तहत के लिए अपीलकर्ताओं एवं अन्य आरोपियों के साथ दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

3. अभियोजन की कहानी, संक्षेप में, जैसा कि अभिलेख में मौजूद तथ्यों पर रखी गई सामग्री से एकत्र की जा सकती है, जो कि इस प्रकार है:

3 नवंबर 2006 की रात, लगभग 07.30 बजे, नरेश कुमार, अभियुक्त संख्या 11 ने आत्माराम (साक्षी सं0 -1) के साथ मारपीट की थी। उक्त हमले के बाद, आत्माराम (साक्षी सं0 -1) रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन, सुहेला गए। इसके बाद, नरेश कुमार, अभियुक्त संख्या 11 ने अन्य आरोपियों के साथ, जो घातक हथियारों से लैस थे, एक विधिविरुद्ध जमाव बनाया और मृतक कार्तिकराम के घर में प्रवेश किया एवं उसके साथ-साथ मंगतिन बाई (साक्षी सं0 -2) तथा खोमलाल (साक्षी सं0 -9) पर हमला किया। उक्त हमले के परिणामस्वरूप कार्तिकराम की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद, मंगतिन बाई (साक्षी सं0 -2), खोमलाल (साक्षी सं0 -9) और पूर्णिमा बाई (साक्षी सं0 -13), क्रमशः मृतक कार्तिकराम की पत्नी, बेटा और बहू, साथ ही पड़ोसी बलिराम साहू (साक्षी सं0 -3) और जीवन लाल साहू (साक्षी सं0 -6) डॉक्टर से इलाज कराने के लिए ट्रैक्टर से बलौदा बाजार गए, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज न होने तक उनका इलाज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक जीप किराए पर ली गई और वे पुलिस स्टेशन सुहेला गए। मौखिक रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) के आधार पर, एक विलय रिपोर्ट (प्रदर्श पी- 10) पंजीकृत की गई। इसके बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, "एफआईआर") दर्ज की गई।

4. उक्त एफआईआर के आधार पर, अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधानकर्ता) इंस्पेक्टर कमल सिंह (साक्षी सं0 -14) ने अनुसंधान किया। अनुसंधान के निष्कर्ष के बाद उन्होंने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बलौदा बाजार के समक्ष 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय था, इसलिए इसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया था।

5. विद्वान विचारणीय न्यायाधीश ने 24 मई 2008 के फैसले और आदेश के तहत सभी अभियुक्त संख्या को पूर्वोक्त रूप से दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 11 नवंबर 2014 के फैसले और आदेश के तहत अभियुक्तों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। उसी को चुनौती देते हुए, इस न्यायालय के समक्ष चार अपीलों दायर की गईं, जिनमें नंद लाल, भागवत और रामदुलार, क्रमशः अभियुक्त संख्या 8 से 10 द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1421/2015 थी; आपराधिक अपील क्रमांक 1422/2015 पलटन जांगड़े द्वारा, अभियुक्त क्रमांक 12; चरणदास जांगड़े, छन्नू जांगड़े और चरनु जांगड़े द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1470/2017 अभियुक्त क्रमांक 5 से 7; और एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6134-6135/2019 से उत्पन्न अपीलों, जो क्रमशः तुलसी जांगड़े, सुरेश जांगड़े, दिनेश जांगड़े, रूपेश जांगड़े और नरेश कुमार, आरोपी संख्या 1 से 4 और 11 द्वारा दायर की गई थीं।

6. अपीलों के लंबित रहने के दौरान , अभियुक्त संख्या 12, पलटन जांगड़े की मृत्यु हो गई है और इस प्रकार, उक्त अपील की आपराधिक अपील संख्या 1422/2015 होने के कारण, इस न्यायालय के आदेश को 13 जनवरी 2023 के आदेश से निरस्त कर दी गई है। तुलसी जांगड़े, एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6134-6135/2019 से उत्पन्न अपील में अपीलकर्ता सुरेश जांगड़े, दिनेश जांगड़े, रूपेश जांगड़े , चन्नू जांगड़े और चरनू जांगड़े और आपराधिक अपील संख्या 1470/2017 में अपीलकर्ता चरणदास जांगड़े सजा पूरी होने पर पहले ही रिहा हो चुके हैं। । इस प्रकार , की आपराधिक अपील संख्या 1421/2015 में अपीलकर्ताओं और एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6134-6135/ 2019 से उत्पन्न अपीलों में अपीलकर्ताओं में से एक नरेश कुमार से संबद्ध हैं।

7. हमने अभियुक्त संख्या 8 से 10 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विकास उपाध्याय, विद्वान न्यायमित्र श्री रेनजिथ बी मरार और प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुमीर सोढ़ी को सुना है।

8. श्री उपाध्याय का कहना है कि अभियुक्त संख्या 8 से 10, यानी नंद लाल , भागवत और रामदुलार के नामों का उल्लेख, किसी भी समसामयिक दस्तावेज़ जैसे मर्ज पंचनामा, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन और घटनास्थलीय पंचनामा में नहीं किया गया है। उनका कहना है कि , जबकि अन्य सभी अभियुक्तों के नाम उपरोक्त दस्तावेज़ों में विशेष रूप से उल्लिखित हैं , इन दस्तावेज़ों में अभियुक्त संख्या 8 से 10 के नामों का कोई उल्लेख नहीं है। यह पहली बार है कि इन तीनों अभियुक्तों का नाम एफआईआर में आया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि हालांकि घटना 3 नवंबर 2006 को रात 08.30 बजे हुई थी, लेकिन एफआईआर 4 नवंबर 2006 को सुबह 03.10 बजे दर्ज की गई थी , जिससे संदेह पैदा होता है कि एफआईआर एक मनगढ़ंत दस्तावेज़ है और मूल एफआईआर अभियोजन पक्ष द्वारा दबा दिया गया एवं उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक देरी के बारे में भी अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सभी तीन साक्षी यानी मंगतिन बाई (साक्षी सं0-2), खोमलाल (साक्षी सं0-9) और पूर्णिमा बाई (साक्षी सं0-13) हितबद्ध साक्षी हैं। आगे कहा गया है कि इन तीन साक्षियों के साक्ष्य भी असंगत हैं। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सजा पूरी तरह से ऐसे हितबद्ध साक्षी के आधार पर थी, जिनकी गवाही ठोस और भरोसेमंद नहीं है , और तब तक पोषणीय नहीं है जब तक कि उनकी गवाही की कुछ पुष्टि न हो।

9. श्री उपाध्याय का कहना है कि , किसी भी मामले में , सभी तीन चश्मदीद गवाहों , यानी मंगतिन बाई (साक्षी सं0-2), खोमलाल (साक्षी सं0-9) और पूर्णिमा बाई (साक्षी सं0-13) ने यहां अपीलकर्ताओं के खिलाफ केवल सर्वव्यापी आरोप लगाए हैं और वर्तमान अपीलकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराने हेतु किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि

घटना रात में हुई और यह भी स्वीकार किया गया कि बिजली कटौती हुई थी। ऐसे में तीनों साक्षियों की यह साक्ष्य कि उन्होंने घटना को चांदनी रात में और दीपक की रोशनी में देखा था , विश्वसनीय नहीं कही जा सकती। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि , चूंकि साक्षी सं0-9 ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसने खुद को एक अनाज-भंडार (कोठी) में छिपाया था , इसलिए यह असंभव है कि उसने इस घटना को देखा हो।

10. श्री मरार का कहना है कि वास्तव में , अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी सं0-14, अनुसंधानकर्ता ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार के सिर, बाएं पैर के टखने और दाहिने हाथ की मध्य उंगली पर चोटें थीं। उन्होंने कहा कि विचारण न्यायालय ने भी पाया है कि अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार को गंभीर चोटें आई थीं और वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन , सुहेला गए थे। उन्होंने उक्त पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद उन्हें इलाज के लिए भाटापारा अस्पताल भेजा गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार को मिली चोटों के बारे में नहीं बताया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि , किसी भी मामले में, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार से प्राप्त जानकारी को दबा दिया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यह असंभव है कि अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार, इतनी गंभीर चोटें प्राप्त करने के बाद भी, मृतक और साक्षी सं0- 2, 9 और 13 के खिलाफ हमले में भाग ले सकता था।

11. इसके विपरीत, श्री सोढ़ी का कहना है कि तीनों चश्मदीद गवाहों ने सभी अपीलकर्ताओं को स्पष्ट रूप से फंसाया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी सं0 2 और 9 ने विशेष रूप से वर्तमान अपीलकर्ताओं को फंसाया है। यह प्रस्तुत किया गया कि तीनों साक्षी देहाती ग्रामीण हैं। केवल इसलिए कि उनके साक्ष्यों में कुछ विसंगतियां हैं , उनकी साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि केवल इसलिए कि साक्षी , हितबद्ध साक्षी हैं, उनकी साक्ष्यों को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है , अगर उनके साक्ष्य भरोसेमंद , विश्वसनीय और ठोस पाए जाते हैं। श्री सोढ़ी का कहना है कि, किसी भी मामले में, साक्षी घायल साक्षी हैं और इस तरह, घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल इसलिए कि एफआईआर दर्ज करने में कुछ देरी हुई है, यह अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है, जो उचित संदेह से परे साबित हो चुका है।

12. श्री सोढ़ी, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहते हैं कि भा0द0वी0 की धारा 149 की सहायता से भा0द0वी0 की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि के लिए जो प्रासंगिक है वह यह है कि क्या आरोपी विधिविरुध जमाव का सदस्य था, न कि क्या उसने वास्तव में अपराध में

सक्रिय भाग लिया था या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों का स्पष्टीकरण न देना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।

13. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से, हमने अभिलेख पर मौजूद तथ्य की जांच की है।

14. चिकित्सकीय साक्ष्यों से इनकार नहीं किया जा सकता कि मृतक कार्तिकराम की मृत्यु मानव वध है। अपीलकर्ताओं द्वारा साक्षी सं0 2 और 9 की चोटों को भी गंभीरता से विवादित नहीं बनाया गया है।

15. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि घटना दो भागों में घटित हुई है। पहला भाग अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार द्वारा आत्माराम (साक्षी सं0 -1) पर हमले के संबंध में है, जबकि दूसरा भाग अभियुक्तों द्वारा मृतक और साक्षी सं0 2, 9 और 13 पर हमले के संबंध में है। आत्माराम (साक्षी सं0 -1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 3 नवंबर 2006 को, जब वह अपने घर पर था, अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार उसके घर आया और उसे गाली देना शुरू कर दिया। साक्षी सं0 -1 ने कहा कि अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार शराब के नशे में था। अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार ने साक्षी सं0 -1 को बताया कि वह शिकायत करने के लिए उसके घर गया था और उसने उसे शराब पिलाकर 5,000/- रुपये की राशि वसूल की थी। इसके बाद अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार ने लाठी से साक्षी सं0 -1 पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर, साक्षी सं0 -1 का कहना है कि अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार इस धमकी के साथ वहाँ से चला गया कि वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वापस आयेगा। आत्माराम (साक्षी सं0 -1) द्वारा आगे कहा गया है कि, इसके बाद, वह अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ सुहेला पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने गए।

16. आत्माराम (साक्षी सं0 -1) ने आगे कहा कि जब वह पुलिस स्टेशन से लौटा, तो उसके बेटे ने आकर उसे बताया कि साक्षी सं0 -1 के पिता की हत्या कर दी गई थी और साक्षी सं0 -1 रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए फिर से पुलिस स्टेशन गया। ऐसे में यह स्पष्ट है कि साक्षी सं0 -1 दूसरी घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है।

17. मंगतिन बाई (साक्षी सं0 -2) मृतक कार्तिकराम की पत्नी है। उसने अपनी साक्ष्य में कहा कि सभी अभियुक्त उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। उनके पति टीवी रूम में थे, उक्त टीवी रूम में सभी अभियुक्त उसके पति के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद वे दूसरे कमरे में आये जहाँ कोई नहीं था, उसके बेटे ने खुद को धान की कोठी में छुपा लिया था। अभियुक्त वहाँ पहुंचे और उसके बेटे के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद, वह अपने पड़ोसी जीवन लाल साहू (साक्षी सं0 -6) को सूचित करने गईं। वह, साक्षी सं0 9 और 13 के साथ, फिर एक

ट्रैक्टर से बलौदा बाजार गई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज न होने के कारण वे लोग अपना इलाज नहीं करवा सके। वे वहां से जीप लेकर सुहेला थाने गए। वहां से उन्हें इलाज के लिए भाटापारा अस्पताल ले जाया गया।

18. मंगतिन बाई (साक्षी सं0 -2) से जिरह में यह पूछे जाने पर कि क्या वह अदालत में मौजूद अभियुक्तों के रिश्तेदारों को जानती है, उसने कहा कि वह उन्हें जानती है लेकिन वह उनका नाम नहीं बता सकती।

19. खोमलाल (साक्षी सं0 -9) मृतक कार्तिकराम का घायल पुत्र है। उनका साक्ष्य भी इसी प्रकार का है। वह भी आत्माराम (साक्षी सं0 -1) से संबंधित पिछली घटना के बारे में गवाही देता है। उनका कहना है कि रात लगभग 08.30 बजे आत्माराम (साक्षी सं0 -1) के पुलिस स्टेशन जाने के बाद, सभी अभियुक्त उसके घर आये। उसका कहना है कि सभी अभियुक्त उसके पिता के कमरे में घुस गये और उसके पिता के साथ मारपीट करने लगे इसलिए, वह धन की कोठी में छिपने के लिए चला गया। अभियुक्तों ने वहां आकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इसके बाद वे इलाज के लिए बलौदाबाजार चले गए। हालांकि, डॉक्टर ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया। ऐसे में वे सुहेला थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। अपनी जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा दर्ज कराई गई मर्ज रिपोर्ट में नंदलाल, भगवंत और रामदुलार यानी अभियुक्त संख्या 8 से 10 तक का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को सारी जानकारी दे दी है, लेकिन केवल पुलिस ही बता सकती है कि उपरोक्त तीन अपीलकर्ताओं के नाम इसमें क्यों नहीं हैं।

20. खोमल (साक्षी सं0 -9) की पत्नी पूर्णिमा (साक्षी सं0 -13) का यह भी कहना है कि आत्माराम (साक्षी सं0 -1) शाम करीब 7:00 बजे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा था। वह बताती है कि, रात 8:00 बजे से 8:30 बजे के बीच, अभियुक्त, अर्थात् चरणदाद जांगड़े, तुलसी जांगड़े, चरनू जांगड़े, भागवत और अन्य लोग उनके घर आए, जहां उन्होंने पहले उसकी सास मंगतिन बाई (साक्षी सं0 -2) पर डंडे से हमला किया। इसके बाद वह मंगतिन बाई (साक्षी सं0 -2) और खोमलाल (साक्षी सं0 -9) द्वारा दिए गए संस्करण को दोहराती है।

21. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "सी.आर. पीसी") की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में, अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार ने विशेष रूप से कहा कि आत्माराम (साक्षी सं0 -1) द्वारा हमला किए जाने के बाद उसे गंभीर चोटें आई थीं और उसके बाद वह अभियुक्त संख्या 7 चरनू जांगड़े, अभियुक्त संख्या 12 पलटन जांगड़े, अश्विनी और विनोद के साथ पुलिस स्टेशन गया, जहां से उसे इलाज के लिए भाटापारा अस्पताल भेजा गया।

22. डॉ. अनिता वर्मा (साक्षी सं0 -10) द्वारा अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार की चिकित्सकीय जाँच का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। उन्हें लगी चोटें इस प्रकार हैं:

- “खोपड़ी के बाएं पार्श्विका क्षेत्र पर 6x1x0.5 सेमी का क्षत-विक्षत घाव।
- पीठ, बाएँ कंधे, बाएँ हाथ पर कई चोटें, जिनका आकार लंबाई में 5 से 20 सेमी और चौड़ाई में 2 से 4 सेमी तक होता है।
- बाएं पैर पर 3x0.5 सेमी का घर्षण।
- प्रॉक्स पर सूजन, कोमलता और विकृति दाहिनी मध्यमा उंगली का फालानक्स।
- माथे पर 2x0.2 सेमी का घर्षण।
- माथे के बाईं ओर 1 x0.2 सेमी का घर्षण।
- दाहिने टखने पर 2x0.5 सेमी का घर्षण।
- बाईं पार्श्विका हड्डी का फ्रैक्चर, • बाएं कंधे में फ्रैक्चर।
- मध्यमा अनामिका के समीपस्थ फालानक्स का फ्रैक्चर।
- ऊपरी 1/3 और मध्य 1/3 जंक्शन पर फाइबुला के शाफ्ट का फ्रैक्चर।

23. साक्षी सं0 -14, अनुसंधानकर्ता स्वीकार करता है कि मर्ज सूचना प्रतिवेदन में नंद लाल , भागवत और रामदुलार यानी क्रमशः अभियुक्त संख्या 8 से 10 के नाम का उल्लेख नहीं है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि घटनास्थलीय पंचनामा में भी उनके नाम का उल्लेख नहीं है। वह अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि पूर्व में डी-9, अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार के साथ घटना 3 नवंबर 2006 को रात 08.30 बजे घटित होने का उल्लेख है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार के सिर, बाएं पैर के टखने और दाहिने हाथ की उंगली बीच में गंभीर चोटें थीं। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि रात 11.45 बजे नरेश कुमार को जांच के लिए थाने से डॉक्टर के पास ले जाया गया।

24. इस प्रकार साक्षी सं0 -14, अनुसंधानकर्ता के साक्ष्य से यह देखा जा सकता है कि पुलिस को घटना के बारे में कम से कम 3 नवंबर 2006 को रात 11.45 बजे से पूर्व जानकारी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगी। एफआईआर दर्ज करने में विलम्ब का प्रभाव प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भिन्न होगा। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार को गंभीर चोटें आई

थीं, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार द्वारा एक विशिष्ट बचाव किया गया है कि जब वह शराब पीकर आ रहा था, तो आत्माराम (साक्षी सं0 -1) द्वारा उस पर हमला किया गया था। इसके बाद वह अभियुक्त संख्या 7 चरनू जांगड़े, अभियुक्त संख्या 12 पलटन जांगड़े, अश्विनी और विनोद के साथ पुलिस स्टेशन गया, जिसके बाद उसे चिकित्सकीय जाँच के लिए भेज दिया गया। अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार की चोटों को देखकर यह मुश्किल लग रहा है कि वह घटना के दूसरे हिस्से में शामिल हो सकता था। अभियोजन पक्ष ने आत्माराम (साक्षी सं0 -1) के साथ-साथ अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार द्वारा दर्ज की गई पहली रिपोर्ट को दबा दिया है। यदि रात 11.45 बजे नरेश कुमार की जांच की गई, तो कम से कम 11.00 बजे तक पुलिस को घटना के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। ऐसे में एफआईआर दर्ज करने में कम से कम चार घंटे की विलम्ब हो जाती है।

25. एफआईआर की अंतर्निहित तथ्यों पर विश्वास करते हुए कि घटना लगभग 08.30 बजे रात में हुई थी और घायल व्यक्ति लगभग 10-11 बजे रात में बलौदा बाजार पहुंचे थे, जहां उन्हें सूचित किया गया था कि जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, तब तक उनका इलाज नहीं किया जा सकता है। एफआईआर दर्ज करने में लगभग चार से पांच घंटे की और विलम्ब का कारण नहीं बताया गया है। बलौदा बाजार और सुहेला थाने के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यह अभिलेख में आया है कि दोनों स्थानों को जोड़ने वाली एक बारहमासी सड़क है। ऐसे में बलौदा बाजार से सुहेला थाना पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट का समय लगेगा। एफआईआर दर्ज करने में हुई चार घंटे की विलम्ब को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

26. हम पहले अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने के संबंध में मुद्दे पर विचार करेंगे। लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में जो की भा0द0वी0 की धारा 149 के साथ पढ़ी गई धारा 302 के तहत दोषसिद्धि से उत्पन्न हुआ था जहाँ इस न्यायालय के पास के गैर-स्पष्टीकरण के मुद्दे पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए इस प्रकार कहा:

“12. हमें ऐसा लगता है कि एक हत्या के मामले में, घटना के समय या विवाद के दौरान अभियुक्त को लगी चोटों का स्पष्टीकरण न देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिससे अदालत निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकती है:

“(1) अभियोजन पक्ष ने घटना के कारण और उत्पत्ति को दबा दिया है और इस प्रकार सही संस्करण प्रस्तुत नहीं किया है;

(2) जिन गवाहों ने अभियुक्त के शरीर पर चोटों की उपस्थिति से इनकार किया है, वे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं और इसलिए उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है;

(3) यदि कोई बचाव संस्करण है, जो अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों की व्याख्या करता है तो इसे अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करने के लिए संभावित बनाया गया है।

अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों के बारे में अभियोजन पक्ष की ओर से स्पष्टीकरण न देना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां साक्ष्य में रुचि रखने वाले या शत्रुतापूर्ण साक्षी शामिल होते हैं या जहां बचाव पक्ष एक संस्करण देता है जो अभियोजन पक्ष के संस्करण के साथ संभावना में प्रतिस्पर्धा करता है। मौजूदा मामले में, जब यह माना जाता है, जैसा कि होना चाहिए, कि अपीलकर्ता दशरथ सिंह को गंभीर चोटें आईं, जिसका अभियोजन पक्ष ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तो अदालत के लिए साक्षी सं0 1 से 4 और 6 के साक्ष्य पर भरोसा करना मुश्किल होगा, विशेष रूप से जब इनमें से कुछ गवाहों ने यह कहकर झूठ बोला है कि उन्होंने अभियुक्त के शरीर पर कोई चोट नहीं देखी है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि न तो सत्र न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय ने अभियोजन मामले में दिखाई देने वाली इस महत्वपूर्ण कमी या कमजोरी पर उचित विचार किया है। हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि जैसा कि इस न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम बाई फातिमा [(1975) 2 एससीसी 7: 1975 एससीसी (सीआरआई) 384] में कहा था, ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का गैर-स्पष्टीकरण का अभियोजन पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से उन मामलों पर लागू होगा जहां अभियुक्त को लगी चोटें मामूली और सतही हैं या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस, इतना स्वतंत्र और उदासीन, इतना संभावित, सुसंगत और विश्वसनीय है कि यह चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन पक्ष की चूक के प्रभाव से कहीं अधिक है। हालाँकि, वर्तमान में, निश्चित रूप से ऐसा कोई मामला नहीं है, और इसलिए, उच्च न्यायालय ने असंबद्ध आधार पर अभियोजन मामले में इस गंभीर कमजोरी को दूर करने में गलती की थी।"

27. चोटों के गैर-स्पष्टीकरण के संबंध में इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम माधो और अन्य², एमपी राज्य बनाम मिश्रीलाल (मृत) और अन्य और नागरथिनम और अन्य बनाम राज्य (पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व) के मामलों में लिया गया है।

28. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार को लगी चोटों को मामूली या ऊपरी नहीं माना जा सकता है। साक्षी भी हितबद्ध साक्षी होते हैं, क्योंकि वे मृतक के करीबी रिश्तेदार होते हैं। यह बात सामने आई है कि दोनों परिवारों के बीच सरपंच के चुनाव को लेकर पहले से दुश्मनी थी। जैसा कि इस न्यायालय ने रामाशीष राय बनाम जगदीश सिंह के मामले में देखा था, पिछली दुश्मनी एक दोधारी तलवार है। एक ओर, यह मकसद प्रदान कर सकता है और दूसरी ओर, गलत निहितार्थ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

29. हम यहां अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार को लगी चोटों को पहले ही देख चुके हैं। खोमलाल द्वारा 4 नवंबर 2006 को सुबह 03.15 बजे एफआईआर दर्ज कराने से काफी पहले पुलिस अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार को चिकित्सकीय जांच के लिए ले गई थी। अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार को चिकित्सकीय जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी को अग्रेषित करने वाले मेमो में उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त संख्या 11 ने पुलिस को सूचित किया था कि रात लगभग 08.30 बजे, आत्माराम (साक्षी सं0-1) द्वारा उस पर हमला किया गया था। निर्विवाद रूप से, अभियोजन पक्ष ने उक्त घटना के संबंध में जानकारी दबा दिया है। उक्त घटना के संबंध में जानकारी अभियोजन पक्ष ने आत्माराम (साक्षी सं0-1) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को भी दबा दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दबाने का प्रयास किया है। मामले के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार को लगी चोटों के गैर-स्पष्टीकरण के साथ, हमारा विचार है कि अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार संदेह के लाभ का हकदार है।

30. अब अन्य 3 आरोपियों, अर्थात् अभियुक्त संख्या 8 नंदलाल, अभियुक्त संख्या 9 भागवत और अभियुक्त संख्या 10 रामदुलार की अपील विचारण के लिए बचता है। उनके मामले पर विचार करने के लिए हमें एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को भी ध्यान में रखना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक मामले में, एफआईआर दर्ज करने में देरी अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं होगी। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, यह मानते हुए कि घटना रात 08.30 बजे हुई थी और घायल व्यक्ति रात 10-11 बजे के बीच बलौदा बाजार में थे, और यह ध्यान में रखते हुए कि बलौदा बाजार से सुहेला पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, एफआईआर दर्ज करने में चार घंटे की देरी अभियोजन पक्ष के मामले की वास्तविकता पर गंभीर संदेह पैदा करेगी। यह और भी स्पष्ट हो जाता है क्योंकि अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार ने किसी भी मामले में पुलिस को घटना के बारे में रात 11.45 बजे से पूर्व सूचित किया था। आत्माराम (साक्षी सं0-1) द्वारा उस पर किए गए हमले के संबंध में उसके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को दबाना, साथ ही अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार के खिलाफ आत्माराम (साक्षी सं0-1) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को दबाना, संदेह को बढ़ाता है।

31. हम रमेश बाबूराव देवस्कर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का लाभ उठा सकते हैं:

“19. इस प्रकृति के मामले में, दो समूहों के बीच दुश्मनी स्वीकार की जाती है। इस प्रकृति की स्थिति में, प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व-समय पर थी या नहीं, इस पर भी गंभीरता से विचार करने

की आवश्यकता है। इस प्रकृति के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट , एक मूल्यवान साक्ष्य प्रदान करती है, हालाँकि यह पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो सकता है। बिना किसी देरी के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर जोर देने का कारण उन परिस्थितियों के संबंध में पहले की जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया था , आरोपियों का नाम , उनके द्वारा निभाई गई भूमिका , जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और चश्मदीनों के नाम भी। जहां पार्टियों में मतभेद हो और ऐसी घटनाएं हुई हों जिसके परिणामस्वरूप एक या दूसरे की मृत्यु हुई हो , प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि इस न्यायालय ने माना है , एफआईआर एक मूल्यवान सबूत है, हालांकि यह पर्याप्त सबूत नहीं हो सकता है। तत्काल एफआईआर दर्ज करने से कई लोगों के शामिल होने का संदेह दूर हो जाता है , खासकर जब मामले में दो समूहों के बीच लड़ाई शामिल हो। जब दोनों पक्षों के बीच मतभेद होता है , तो तत्काल एफआईआर दर्ज करने से अभियोजन पक्ष को विश्वसनीयता मिलती है।

32. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामला हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें से दो घायल साक्षी हैं। इस न्यायालय ने , वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य के मामले में, इस प्रकार देखा है:

"11..... इसलिए, हमारी राय में, यह कानून का एक मजबूत और अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि अदालत किसी तथ्य को साबित करने या अस्वीकार करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा के बारे में नहीं , बल्कि गुणवत्ता के बारे में चिंतित है। सामान्यतया, इस संदर्भ में मौखिक साक्ष्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:

(1) पूर्णतः विश्वसनीय।

(2) पूर्णतः अविश्वसनीय।

(3) न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय।

12. सबूत की पहली श्रेणी में , अदालत को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए - वह किसी एक साक्षी की साक्ष्य पर उसे दोषी ठहरा सकती है या बरी कर सकती है , यदि वह निंदा या रुचि , अक्षमता या अधीनता के संदेह से ऊपर पाया जाता है। दूसरी श्रेणी में भी न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह मामलों की तीसरी श्रेणी में है, कि अदालत को सतर्क रहना होगा और विश्वसनीय साक्षियों, प्रत्यक्ष साक्षियों या परिस्थितिजन्य साक्षियों, द्वारा भौतिक विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होगी..."

33. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि "पूर्णतः विश्वसनीय" साक्षी की श्रेणी में , अभियोजन पक्ष को ऐसे साक्षी की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि के लिए दबाव डालने में कोई कठिनाई नहीं

होती है। "पूरी तरह से अविश्वसनीय" साक्षी के मामले में , फिर से, कोई कठिनाई नहीं है , क्योंकि "पूरी तरह से अविश्वसनीय" साक्षी द्वारा प्रदान की गई मौखिक गवाही के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। वास्तविक कठिनाई तीसरी श्रेणी के साक्ष्य के मामले में आती है जो आंशिक रूप से विश्वसनीय और आंशिक रूप से अविश्वसनीय है। ऐसे मामलों में, अदालत को सतर्क रहने और अनाज से भूसी को अलग करने और प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य , विश्वसनीय गवाही से आगे की पुष्टि की मांग करने की आवश्यकता होती है।

34. निर्विवाद रूप से , वर्तमान मामले में , साक्षी सं0 2 और 9 घायल साक्षी हैं। ऐसे में उनकी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता। हालाँकि, जैसा कि यहाँ पहले ही देखा जा चुका है , पिछली दुश्मनी साबित होने की स्थिति में, झूठे आरोप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, यह देखा जाएगा कि अभियुक्त संख्या 12 पलटन जांगड़े के पूरे परिवार को इसमें शामिल किया गया है। हालांकि साक्षी सं0 -2 ने अपनी जिरह में आरोपी की पहचान की है और उसका नाम बताया है , उसने कहा है कि , हालांकि उसने अभियुक्तों के रिश्तेदार को पहचान लिया था, परन्तु उसे उनके नाम याद नहीं हैं। ऐसे में पलटन के पूरे परिवार के फंसने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

35. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है , मर्ज प्रतिवेदन में नंद लाल , भागवत और रामदुलार के नाम का उल्लेख नहीं है , जो एफआईआर दर्ज करने से पहले दर्ज किया गया था , इसलिए उनके नाम मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन और घटनास्थलीय पंचनामे में भी नहीं पाए गए हैं। प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी और समसामयिक दस्तावेजों में उनके नाम का उल्लेख नहीं होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त अभियुक्तों को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे विचार में, पर्याप्त पुष्टि के बिना , केवल हितबद्ध साक्षियों की मौखिक साक्ष्य के आधार पर इन अभियुक्तों की सजा पोषणीय नहीं होगी।

36. अभियोजन पक्ष ने बलिराम साहू (साक्षी सं0 -3), इंदर साहू (साक्षी सं0 -5), जीवन लाल (साक्षी सं0 -6) और बुधेराम (साक्षी सं0 -8) से पूछताछ की है, जिनमें से किसी ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। साक्षी सं0 2, 9 और 13 के अनुसार, यह साक्षी बलिराम साहू (साक्षी सं0 -3) था जिसने घायल व्यक्तियों को बलौदा बाजार ले जाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की थी। हालाँकि, उन्होंने कहा है कि मंगतिन बाई (साक्षी सं0 -2) उन्हें घटना के बारे में सूचित करने के लिए उनके पास आई थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें यह नहीं बताया था कि किस आरोपी ने मृतक और घायल व्यक्तियों के साथ मारपीट की थी। इसलिए, हमारे विचार में, उक्त अपीलकर्ता भी संदेह का लाभ पाने के हकदार होंगे।

37. इसलिए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता नंद लाल , भागवत, रामदुलार और नरेश कुमार संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

38. फलस्वरूप, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

(i) अपीलें स्वीकार की जाती हैं;

(ii) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 11 नवंबर 2014 का निर्णय एवं आदेश, एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24 मई 2008 निर्णय और आदेश को अभीखंडन एवं निरस्त किया जाता है।

(iii) अपीलकर्ताओं को लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

39. यदि कोई लंबित आवेदन (आवेदनों) हो तो इसे निष्पादित समझा जाएगा।

40. फैसले की समाप्ति के पूर्व, हमें अभियुक्त संख्या 8 से 10 की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री विकास उपाध्याय और अभियुक्त संख्या 8 से 10 की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री सुमीर सोढ़ी द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करनी चाहिए। प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री रेनजिथ बी मरार द्वारा किए गए श्रमसाध्य प्रयासों का विशेष उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है , जिन्हें उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अभियुक्त संख्या 11 के लिए न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था।

रंजीत कुमार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश, जामताड़ा